Title: Need to roll-back the hike in the tariff of land-line telephones in the country.

श्री सुरेश रामराव जाधव (परभनी) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से अपील करना चाहता हूँ कि सरकार ने आगामी 1 अप्रैल से शहरी और ग्रामीण दोनों जगहों पर स्थायी टैलीफोन दरों में वृद्धि करने का निर्णय किया है। एक ओर सैलफोन की दरें कम की जा रही हैं और दूसरी ओर स्थायी टैलीफोन जो आम जनता और ग्रामीण तथा गरीब लोगों के लिए एक जरूरत की चीज़ है, उसकी दरों में भारी वृद्धि की जा रही है। वास्तविकता यह है सैलफोन की दरें कम करके लोगों को उस ओर जाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि लोग स्थायी टैलीफोन को कटवाकर सैलफोन ले लें। इससे न केवल सरकारी टैलीफोन विभाग का दीवाला पिट जाएगा, बल्कि कुछ समय बाद बहुराट्रीय कंपनियां मनमाना किराया वसूल करेंगी। मैं सदन के माध्यम से सरकार से अपील करूँगा कि वह आम जनता के इस भारी रोा के मद्देनज़र इस मुद्दे पर पुनर्विचार करे और टैलीफोन दरों में वृद्धि का जो निर्णय लिया है, उसको तुरन्त वापस ले।

MR. SPEAKER: Shri Shankar Prasad Jaiswal − Not present.

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण मध्य) : अध्यक्ष महोदय, मैंने भी नोटिस दिया है।

श्री मोहन रावले : अध्यक्ष महोदय, सरकार टेलीफोन का मासिक किराया 250 रुपए से बढ़ाकर 280 रुपए करने जा रही है। इसी के साथ 3 मिनट की एक कॉल का समय घटाकर 2 मिनट कर रही है। पहले एक महीने में 75 कॉल फ्री थीं और अब इनकी संख्या घटाकर 30 करने जा रही है। इस प्रकार से प्रतिमाह 45 फ्री कॉल कम की जा रही हैं। तीन से दो मिनट काल टाइम कम करने से प्रति माह 82 कॉल का पैसा उपभोक्ता को ज्यादा देना पड़ेगा। पहले 1000 कॉल करने पर जहां 1325 रुपए देने पड़ते थे, वहां अब रेट बढ़ने के बाद 2025 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे। इस प्रकार से उपभोक्ता के ऊपर प्रति माह लगभग 695 रुपए ज्यादा का बोझ बढ़ाया जा रहा है, यानी 52 प्रतिशत दाम बढ़ जाएंगे। इसकी वजह से एम.टी.एन.एल. सरकार की कंपनी बन्द हो जाएगी और उसके बन्द होने पर 65,000 वर्कर्स सड़क पर आ जाएंगे।

अध्यक्ष महोदय, सरकारी कंपनी की डालफिन सेवा के मार्केट में आने से सैल्यूलर टेलीफोन के दाम जो पहले 16 रुपए प्रति मिनट थे वे घट कर अब रु.1.49 प्रति मिनट रह गए हैं। इससे स्पट होता है कि एम.टी.एन.एल. के कारण दामों में भारी गिरावट आ गई जिससे उपभोक्ता को लाभ हुआ। इसमें कंपटीशन होना चाहिए यह अच्छी बात है, लेकिन सरकारी कंपनी एम.टी.एन.एल. को भी कंपटीशन में आने की इजाजत देनी चाहिए। मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर से प्रार्थना करता हूं कि सरकार टेलीफोन के जो दाम बढ़ाने जा रही है, उसे रद्द किया जाए। इसके लिए एम.टी.एन.एल. को अपनी टैक्नौलौजी अपग्रेड करने के लिए इक्विपमेंट्स खरीदने चाहिए जिससे इस सार्वजनिक सेवा का फायदा आम जनता को हो सके।

अध्यक्ष महोदय : जायसवाल जी बार-बार बोल रहे थे कि उनका विाय बहुत महत्वपूर्ण है। वे नहीं हैं?

Shri Subodh Mohite − Not present.

People are giving notices and they remain absent in the House. It is not at all good. It is not desirable that the Members remain absent when their notices come up for discussion.